खुशखबरी! पीएम आवास की नई लिस्ट जारी, 81 परिवारों को पक्के मकान

विषय सूची (Table of Contents):

>> पीएम आवास योजना की दूसरी सूची जारी कोपरा में 81 परिवारों को मिली पक्के मकान की ...
>> शहरी गरीब परिवारों को मिलेगा सुरक्षित आशियाना...
>> 6 महीने पहले 88 परिवारों को मिला था लाभ, अब तक कुल 169 आशियानों को मिली स्वीकृति...
>> चरणबद्ध तरीके से मिल रहा है विकास योजनाओं का लाभ...
>> जल्द मिलेगी पहली किस्त बैंक खाता सीडिंग और भूमि सत्यापन की प्रक्रिया शुरू...
>> पारदर्शी भुगतान व्यवस्था और पहली किस्त का आवंटन...
>> लाभार्थियों में खुशी की लहर मौसम की मार और जर्जर मकानों के खतरे से मिलेगी हमेशा...
>> असुरक्षा और आपदाओं से मिलेगी मुक्ति...
>> लगातार प्रयासों का दिखा असर जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से गरीबों का सपना हुआ सा...
>> प्रशासनिक सतर्कता और जनहित के कार्य...
>> नगर पंचायत अध्यक्ष रूप नारायण साहू का बयान हमारा लक्ष्य है कि कोई भी परिवार कच...
>> भविष्य की योजनाएं और पारदर्शी कार्यशैली...
>> तेजी से होगा काम समय पर राशि आवंटन और जल्द निर्माण पूरा करने के लिए प्रशासन मुस...
>> आधुनिक भारत और तेजी से बदलता इंफ्रास्ट्रक्चर...
>> निष्कर्ष कोपरा में खुशहाली और सम्मानजनक जीवन का नया सवेरा...
>> महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर...

पीएम आवास योजना की दूसरी सूची जारी: कोपरा में 81 परिवारों को

छत्तीसगढ़ के राजिम क्षेत्र अंतर्गत स्थितकोपरा नगर पंचायतके आवासहीन और जरूरतमंद परिवारों के लिए वर्षों का लंबा इंतजार अब आखिरकार समाप्त हो चुका है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षीप्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)के तहत जारी की गई दूसरी सूची में नगर के 81 नए पात्र हितग्राहियों को पक्के मकानों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

इस नई सूची के जारी होने से स्थानीय निवासियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बुनियादी सुविधाओं से वंचित और कच्चे मकानों में गुजर-बसर कर रहे गरीब परिवारों के लिए यह फैसला किसी वरदान से कम नहीं है।PMAY List 2026की इसlatest updateके बाद स्थानीय प्रशासन तेजी से आगे की कार्रवाई में जुट गया है।

शहरी गरीब परिवारों को मिलेगा सुरक्षित आशियाना

प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य हर गरीब और बेघर परिवार को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और पक्की छत मुहैया कराना है। कोपरा नगर पंचायत क्षेत्र में लगातार किए जा रहे सर्वेक्षणों और आवेदनों की जांच के बाद इन 81 परिवारों का चयन किया गया है।

नगर पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चयनित सभी परिवार योजना के तय मानकों पर खरे उतरे हैं। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ताकि लाभार्थियों को समय पर योजना का सीधा लाभ मिल सके।

6 महीने पहले 88 परिवारों को मिला था लाभ, अब तक कुल 169 आशियाना

कोपरा नगर पंचायत क्षेत्र में पक्के आशियाने का दायरा दिन-ब-दिन तेजी से विस्तार ले रहा है। उल्लेखनीय है कि लगभग छह महीने पहले ही इस क्षेत्र के 88 जरूरतमंद परिवारों को योजना के पहले चरण में पक्के मकानों की स्वीकृति दी गई थी।

अब दूसरी सूची में 81 नए हितग्राहियों के नाम शामिल होने के बाद कोपरा नगर पंचायत में पक्के मकान पाने वाले कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर169 परिवारहो गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि क्षेत्र के 169 गरीब परिवारों का अपना पक्का घर होने का सपना अब वास्तविकता में बदल रहा है।

चरणबद्ध तरीके से मिल रहा है विकास योजनाओं का लाभ

क्षेत्र में चरणबद्ध विकास के चलते अब बुनियादी ढांचा काफी मजबूत हो रहा है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का असर जमीनी स्तर पर साफ दिखाई दे रहा है। ठीक ऐसे ही, देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी विकास और आवास निर्माण अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे हाल ही मेंगांवों में मकान और पैसों की बारिश! ग्राम रथ अभियान से चमकी किस्मतमें भी ग्रामीण परिवारों को सीधा फायदा पहुंचाया गया था।

जल्द मिलेगी पहली किस्त: बैंक खाता सीडिंग और भूमि सत्यापन की

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के तुरंत बाद नगर पंचायत कार्यालय द्वारा अगली प्रक्रिया तीव्र गति से आरंभ कर दी गई है। सभी 81 चयनित हितग्राहियों केभूमि सत्यापन (Land Verification)औरबैंक खाता आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding)का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया गया है।

भूमि सत्यापन के माध्यम से हितग्राही के पास उपलब्ध भूमि के स्वामित्व की जांच की जाती है, जबकि बैंक खाता सीडिंग से यह

सुनश्चिति होता है कि सरकार द्वारा भेजी जाने वाली सहायता राशि बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पहुंचे।

पारदर्शी भुगतान व्यवस्था और पहली किस्त का आवंटन

प्रशासन का मुख्य लक्ष्य यह है कि सत्यापन प्रक्रिया में कोई अड़चन न आए और पहली किस्त तुरंत जारी हो सके। हितग्राहीPMAY Status Checkऔर भुगतान की स्थिति जानने के लिए नगर पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

>> भूमि सत्यापन:आवेदक के पास प्लॉट या कच्चे मकान की जमीन का सत्यापन।

>> अकाउंट सीडिंग:बैंक खाते को आधार और डीबीटी प्रणाली से जोड़ना।

>> प्रथम किस्त जारी करना:प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू करने के लिए राशि सीधे बैंक खाते में।

लाभार्थियों में खुशी की लहर: मौसम की मार और जर्जर मकानों के

प्रशासनकि स्वीकृति की खबर मिलते ही चयनित 81 परिवारों में उत्सव जैसा माहौल है। वर्षों से टूटे-फूटे, कच्चे और मिट्टी के मकानों में रहने को मजबूर ये परिवार अब एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं। लाभार्थियों ने शासन, प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का दिल से आभार व्यक्त किया है।

कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को हर मौसम में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। मानसून के दौरान छत से पानी टपकने, कड़ाके की ठंड में हवाओं के प्रकोप और भीषण गर्मी में झुलसाने वाली धूप से बचाव का कोई ठोस उपाय नहीं होता था।

असुरक्षा और आपदाओं से मिलेगी मुक्ति

कच्चे और जर्जर मकान न केवल असुरक्षित होते हैं, बल्कि आंधी-तूफान या भारी बारिश में इनके गिरने का खतरा भी लगातार बना रहता है। पक्का मकान बन जाने से इन परिवारों को मौसम की मार से सुरक्षा मिलेगी और वे भयमुक्त होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

लगातार प्रयासों का दिखा असर: जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से ग

कोपरा के गरीब और आवासहीन परिवारों को उनका हक दिलाने के लिए स्थानीय निकाय और जनप्रतिनिधि लगातार प्रयासरत थे।

नगर पंचायत अध्यक्षरूप नारायण साहूऔर स्थानीय पार्षदों ने पात्र हितग्राहियों का सर्वे कराने से लेकर फाइल को प्रशासनिक मंजूरी दिलाने तक हर स्तर पर पैरवी की।

जनप्रतिनिधियों की इस मुस्तैदी और निरंतर फॉलो-अप का ही परिणाम है कि महज 6 महीने के भीतर दूसरी सूची जारी कर 81 और परिवारों का चयन संभव हो सका। जनसेवा और सामाजिक कल्याण के इन कार्यों से नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों में विश्वास बढ़ा है।

प्रशासनिक सतर्कता और जनहित के कार्य

जनप्रतिनिधि न केवल विकास कार्यों को गति दे रहे हैं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने में भी मदद कर रहे हैं। जिस प्रकार स्थानीय विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, उसी प्रकार कानून-व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही मेंकिराना दुकान में टॉफी के साथ बिक रहा था गांजा और बीयर, पुलिस का छापा!जैसी खबरों ने यह स्पष्ट किया है कि प्रशासन समाज को सुरक्षित और अपराधमुक्त बनाने के लिए भी सतर्क है।

नगर पंचायत अध्यक्ष रूप नारायण साहू का बयान: हमारा लक्ष्य है

पीएम आवास की दूसरी सूची जारी होने पर खुशी जताते हुए नगर पंचायत अध्यक्षरूप नारायण साहूने इसे क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक और बड़ी उपलब्धि करार दिया। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

रूप नारायण साहू ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया, हमारा मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोपरा नगर पंचायत क्षेत्र का कोई भी गरीब या जरूरतमंद परिवार कच्चे या जर्जर मकान में रहने के लिए मजबूर न रहे। इन 81 पात्र हितग्राहियों को समय पर वित्तीय सहायता मिले और उनका मकान जल्द से जल्द बनकर तैयार हो, इसके लिए पूरा अमला दिन-रात काम कर रहा है।

भविष्य की योजनाएं और पारदर्शी कार्यशैली

अध्यक्ष ने यह भी आश्वासन दिया कि जो परिवार अभी छूट गए हैं या जिनका आवेदन प्रक्रिया में है, उन्हें भी आगामी सूचियों में प्राथमिकता दी जाएगी। नगर पंचायत का प्रयास रहेगा कि हर पात्र व्यक्ति कोPMAY Online Applyऔर स्वीकृति में पूर्ण सहयोग मिले।

तेजी से होगा काम: समय पर राशि आवंटन और जल्द निर्माण पूरा करन

स्वीकृति मिलने के साथ ही अब निर्माण प्रक्रिया को गति देने का खाका तैयार कर लिया गया है। नगर पंचायत के तकनीकी अधिकारी और इंजीनियर हितग्राहियों के स्थलों का निरीक्षण करेंगे ताकि नियमानुसार मकानों का नक्शा और लेआउट तैयार कराया जा सके।

सरकार की मंशा है कि किस्तों का आवंटन निर्माण की प्रगति के आधार पर समयबद्ध तरीके से किया जाए। इससे न केवल गुणवत्ता बनी रहेगी, बल्कि मकानों का निर्माण कार्य भी निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा हो सकेगा।

आधुनिक भारत और तेजी से बदलता इंफ्रास्ट्रक्चर

देश भर में आवास और ढांचागत सुविधाओं का विस्तार अभूतपूर्व गति से हो रहा है। जिस प्रकार आम जनता को बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं, उसी प्रकार परिवहन और तकनीक में भी देश नए आयाम छू रहा है। इसका बेहतरीन उदाहरण तब देखने को मिला जबबिना डीजल-बिजली दौड़ी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन! जानिए खासियतजैसी अत्याधुनिक तकनीक ने भारतीय रेल के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा।

निष्कर्ष: कोपरा में खुशहाली और सम्मानजनक जीवन का नया सवेरा

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की दूसरी सूची जारी होना कोपरा नगर पंचायत के 81 गरीब परिवारों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आया है। कुल 169 परिवारों को पक्की छत मिलना इस बात का प्रमाण है कि जनहितैषी नीतियां यदि सही नीयत से लागू की जाएं, तो उनका सीधा लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है।

स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मुस्तैदी से यह उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द इन मकानों का निर्माण पूरा हो जाएगा और ये परिवार अपने नए, सुरक्षित एवं पक्के आशियाने में ससम्मान जीवन यापन कर सकेंगे।

महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर

दूसरी सूची में कोपरा नगर पंचायत क्षेत्र के 81 नए पात्र हितग्राही परिवारों को पक्के मकानों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

6 महीने पहले स्वीकृत 88 परिवारों और वर्तमान दूसरी सूची के 81 परिवारों को मिलाकर कोपरा में कुल 169 परिवारों को पक्के आशियाने की स्वीकृति मिल चुकी है।

भूमि सत्यापन और बैंक खाता आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी होते ही पहली किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी।

बैंक खाता सीडिंग से सरकारी अनुदान की राशि बिना किसी मध्यस्थ या गड़बड़ी के सीधे लाभार्थी के प्रमाणित बैंक खाते में सुरक्षित रूप से जमा होती है।

आप प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाकर Search Beneficiary विकल्प चुनकर अपने नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर से लिस्ट चेक कर सकते हैं।

जी हां, आधिकारिक पोर्टल पर राज्य, जिला, निकाय और वार्ड का चयन करके लाभार्थी सूची का PDF डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय नगर पंचायत कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

भूमि सत्यापन के लिए जमीन के पट्टे विलेख की प्रति, खसरा खतौनी, बिजली बिल, आधार कार्ड और वर्तमान कच्चे घर का फोटो आवश्यक होता है।

पीएम आवास योजना (शहरी) के बीएलसी (Beneficiary Led Construction) घटक के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए कुल 2.50 लाख की आर्थिक सहायता चरणों में दी जाती है।

छूटे हुए पात्र परिवार अपनी स्थानीय नगर पंचायत कार्यालय या नजदीकी सीएससी (CSC Center) के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ PMAY Urban Portal पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।

लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल पर Track Your Assessment Status सेक्शन में अपना एप्लीकेशन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करके आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जांच सकते हैं।

प्रशासन का प्रयास है कि सत्यापन व पहली किस्त आवंटन के बाद हितग्राही तुरंत निर्माण कार्य शुरू करें, ताकि आगामी मानसून से पूर्व अधिक से अधिक मकानों का ढांचा बनकर तैयार हो सके।